

भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 149]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 14, 1974/ज्येष्ठ 24, 1896

No. 149]

NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 14, 1974/JYAISTHA 24, 1896

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th June 1974

G.S.R. 270(E) IDRA/30/1/74/8.—Whereas a draft of certain rules further to amend the Registration and Licensing of Industrial Undertakings Rules, 1952, was published as required by sub-section (1) of section 30 of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), at pages 229-231 of the Gazette of India, Extraordinary Part II Section 3, sub-section (i), dated the 8th February, 1974, under the notification of the Government of India in the Ministry of Industrial Development, No. G.S.R. 33(E)/IDRA/30/1/74/2, dated the 8th February, 1974, inviting objections or suggestions from all persons likely to be affected thereby before the 11th March, 1974;

And whereas the said Gazette was made available to the public on the 14th February, 1974;

And whereas no objections and suggestions have been received by the Central Government.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 30 of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Registration and Licensing of Industrial Undertakings Rules, 1952, namely:—

1. These rules may be called the Registration and Licensing of Industrial Undertakings (First Amendment) Rules, 1974.

2. In the Registration and Licensing of Industrial Undertakings Rules, 1952 (hereinafter referred to as the said rules) for the words "Ministry of Industry and

Supply", wherever they occur, the words "Ministry of Industrial Development shall be substituted.

3. For rules 10 and 11 of the said rules, the following rules shall be substituted namely:—

"10. Application to be referred to Committee.—

(1) The Ministry of Industrial Development shall refer the application to a Committee appointed under sub-rule (2),

(2) The Ministry of Industrial Development may, by notification in the Official Gazette, appoint one or more Committees consisting of such number of members as it may think fit to represent—

(a) the Ministries of the Central Government dealing with

(i) the industries specified in the First Schedule to the Act

(ii) Finance;

(iii) Company Affairs; and

(iv) Science and Technology; and

(b) the Planning Commission.

(3) A Committee appointed under sub-rule (2) may co-opt one or more representatives of other Ministries of the Central Government or of any State Government concerned, wherever it is necessary.

11. Submission of report by the Committee.—After such investigation as may be necessary, the Committee to which an application has been referred under rule 10 shall submit a report to the Ministry of Industrial Development".

4. In rule 12 of the said rules, for the words "the Licensing Committee", the words "the committee" shall be substituted.

5. In rule 13 of the said rules for the words "the Licensing Committee", the words and figures "the Committee referred to in rule 11", shall be substituted.

[No. 14(1)L.P. 73]

S. K. SAHGAL, Jt. Secy.

प्रौद्योगिक विकास मंत्रालय

प्रभिसूचना

नई दिल्ली, 14 जून, 1974

सां. कां. निं. 270(प्र)/आईं.डीं.आर.ए. 30/1/74/8.—यतः प्रौद्योगिक उपक्रमों का रजिस्ट्रीकरण और अनुज्ञापन नियम, 1952 में और संशोधन करने के लिए कतिपय नियमों का प्राप्ति, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 30 की उपधारा (1) द्वारा यथा अपेक्षित, भारत सरकार के प्रौद्योगिक विकास मंत्रालय की प्रभिसूचना सं. सां. कां. निं. 33(प्र)/आईं.डीं.आर.ए. 30/1/74/2, तारीख 8 फरवरी, 1974 के अधीन भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (i), तारीख 8 फरवरी, 1974 के पृष्ठ 230-231 पर प्रकाशित किया गया था, जिसमें उन सभी व्यक्तियों से, जिनका उस द्वारा प्रभावित होना सम्भाव्य है, 11 मार्च, 1974 के पूर्व आशेष या सुझाव मांगे गए थे;

और यतः उक्त राजपत्र 14 फरवरी, 1974 को जनता को उपलब्ध-करा दिया गया था;

और यतः केन्द्रीय सरकार द्वारा कोई आशेष और सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं।

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, औद्योगिक उपक्रमों का रजिस्ट्रीकरण और अनुज्ञापन नियम, 1952 में और संशोधन करने के लिए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. इन नियमों का नाम औद्योगिक उपक्रमों का रजिस्ट्रीकरण और अनुज्ञापन (प्रथम संशोधन) नियम, 1974 है।

2. औद्योगिक उपक्रमों का रजिस्ट्रीकरण और अनुज्ञापन, नियम, 1952 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) में, “उद्योग और पूर्ति मंत्रालय” शब्दों के स्थान पर, जहाँ कहीं भी वे आये हों, “औद्योगिक विकास मंत्रालय” शब्द रखे जाएंगे।

3. उक्त नियमों के नियम 10 और 11 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखे जाएंगे अर्थात्:—

“10 आवेदन का समिति को निर्देशित किया जाना:—

- (1) औद्योगिक विकास मंत्रालय आवेदन को उपनियम (2) के अधीन नियुक्त की गई समिति को निर्देशित करेगा।
- (2) औद्योगिक विकास मंत्रालय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा एक या अधिक समितियाँ नियुक्त कर सकेगा जिनमें सदस्यों की उतनी संख्या होगी जितनी वह निम्नलिखित का प्रतिनिधित्व करने के लिए ठीक समझे,—

(क) निम्नलिखित से संबंधित केन्द्रीय सरकार के मंत्रालय—

(i) अधिनियम की प्रथम अनुभूची में विनिर्दिष्ट उद्योग ;

(ii) बिजली ;

(iii) कम्पनी कार्य ; और

(iv) विज्ञान और औद्योगिकी ; तथा

(ख) योजना आयोग

- (3) उपनियम (2) के अधीन नियुक्त की गई समिति, जहाँ कहीं भी आवश्यक हो, केन्द्रीय सरकार के अन्य मंत्रालयों के या किसी सम्बद्ध राज्य सरकार के एक या अधिक प्रतिनिधियों को सहयोजित कर सकेगी।

11. समिति द्वारा रिपोर्ट का प्रस्तुत किया जाना:—ऐसे अन्वेषण के पश्चात्, जो आवश्यक हो, वह समिति जिसको नियम 10 के अधीन आवेदन निर्देशित किया गया है, औद्योगिक विकास मंत्रालय को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।”

4. उक्त नियमों के नियम 12 में, "अनुज्ञापन समिति" शब्दों के स्थान पर "समिति" शब्द रखा जाएगा।

5. उक्त नियमों के नियम 13 में, "अनुज्ञापन समिति" शब्दों के स्थान पर "नियम 11 में निर्दिष्ट की गई समिति" शब्द और अंक रखे जाएंगे।

[सं० 14(1)/ला० पो०/73]

मुरेश कुमार सहगल, संयुक्त सचिव।